|  |  |
| --- | --- |
| **(क)** | क्‍या यह सच है कि वैश्‍विक अनुसंधान फर्म, मैक्‍केरी, के अनुसार भारत का संयुक्‍त राजकोषीय घाटा केंद्र और राज्‍य दोनों का वित्‍त वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) का 8.6 प्रतिशत तक हो जाने की संभावना है तथा इसमें और अधिक चूक होने से क्रेडिट कम होने और व्‍यापारिक विश्‍वास में कमी आने का खतरा है; और |
| **(ख)** | यदि हां, तो सरकार द्वारा राजकोषीय सुधार करने के मार्ग का अनुपालन करने और निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु व्‍यय वृद्धि में कमी लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्‍यौरा क्‍या है? |

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)**

**(क):** बताया गया है कि वैश्‍विक अनुसंधान फर्म मैक्‍वेरी ने इस आशय की टिप्‍पणी की थी।

**(ख):** कई वैश्‍विक संस्‍थाएं और अनुसंधान फर्में अपनी-अपनी प्रणालियों और पूर्वानुमानों के आधार पर विकास और राजकोषीय घाटे का आकलन करती हैं। केंद्र और राज्‍य (संयुक्‍त) का संयुक्‍त राजकोषीय घाटा 2011-12 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्‍पाद का 6.8 प्रतिशत आंका गया है जबकि 2010-11 (संशोधित अनुमान) में यह सकल घरेलू उत्‍पाद का 7.7 प्रतिशत और 2009-10 में सकल घरेलू उत्‍पाद का 9.3 प्रतिशत था। केंद्र का राजकोषीय घाटा 2009-10 के सकल घरेलू उत्‍पाद के 6.4 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 (अनंतिम) में सकल घरेलू उत्‍पाद का 4.7 प्रतिशत रह गया और 2011-12 में इसके और कम होकर सकल घरेलू उत्‍पाद का 4.6 प्रतिशत हो जाने की बजटीय व्‍यवस्‍था है। राज्‍यों (संयुक्‍त) का राजकोषीय घाटा 2009-10 के 2.9 प्रतिशत से गिरकर 2010-11 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्‍पाद का 2.6 प्रतिशत रह गया। 2011-12 में इसके कम होकर सकल घरेलू उत्‍पाद के 2.2 प्रतिशत पर आ जाने की बजटीय व्‍यवस्‍था है। इस तरह, राज्‍यों (संयुक्‍त) ने राजकोषीय घाटे के अधिदेशित लक्ष्‍य के मोर्चे पर पहले ही अच्‍छा प्रदर्शन किया है। राजकोषीय उत्‍तरदायित्‍व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के तहत निर्धारित अधिदेश के अनुसार, भारत सरकार दूसरी तिमाही में प्राप्‍तियों और व्‍यय की प्रवृतियों की समीक्षा करेगी तथा इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत करेगी जिसमें संभावनाओं और राजकोषीय नीति के दृष्‍टिकोण पर प्रकाश डाला जाएगा।

**\*\*\*\***